स्कूल और आंगनवाड़ी अब एक ही परिसर में होंगे

दो विभागों के तालमेल से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की तैयारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 मई. छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत अक्सर एक अनजान जगह से होती है, जहां उनको नया माहौल मिलता है. इस माहौल के डर और झिझक को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को अब एक ही परिसर में लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं

पोषण 2.0 के विजन को धरातल पर उतारने के लिए केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है. अब आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों का को-लोकेट किया जा रहा है. इस व्यावहारिक रणनीति का उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और देखभाल की एक ऐसी मजबूत नींव रखना है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल दो संस्थानों को एक परिसर में लाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित, प्रेरक और उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल तैयार करने का महाअभियान है.

क्या बदलेगा इस व्यवस्था से..?

यह को-लोकेशन मॉडल मुख्य रूप से उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू किया जा रहा है जो प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थित हैं और जहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित पहुँच उपलब्ध है. इसमें अस्थायी या सीमित संसाधनों वाले परिसरों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरित कर अधिक सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे विद्यालय जहाँ अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं, वहां आंगनवाड़ी केंद्रों को को-लोकेट किया जा रहा है जिससे शासकीय परिसंपत्तियों और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके. भौगोलिक कारणों से जिन क्षेत्रों में भौतिक रूप से को- लोकेशन संभव नहीं है, वहां समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है जिससे दोनों संस्थानों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

> इस एकीकृत मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों से पहली कक्षा में स्थानांतरण बेहद सुचारू और सहज हो जाएगा. विद्यालय परिसर से पहले से परिचित होने के कारण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे शुरुआती कक्षाओं में होने वाले ड्रॉप आउट की दर में भारी कमी आएगी. इस नई व्यवस्था से आंगनवाड़ी के बच्चों को स्कूलों की आधुनिक अधोसंरचना, खेल के मैदानों और उन्नत शैक्षणिक संसाधनों तक समान पहुंच मिलेगी. बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने के साथ-साथ खेल-आधारित पाठ्यक्रमों जैसे आधारशिला और जादुई पिटारा के साझा उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा. आंगनवाड़ी एवं विद्यालीन समन्वय से बच्चों के डेटा का मिलान आसान होगा, जिससे सेवाओं के दोहराव से बचा जा सकेगा और प्रत्येक बच्चे तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो.

जाबाली योजना में अब नए क्षेत्र भी शामिल होंगे

भोपाल. प्रदेश में वैश्यावृत्ति का दंश झेल रही महिलाओं को इसके दायरे से बाहर लाने के लिए प्रदेश में संचालित जाबाली योजना में नए जिले और क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा. अभी ये योजना प्रदेश के चुनिंदा जिलों में संचालित हैं, जहां वैश्यावृत्ति के मामले ज्यादा आते हैं. मंगलवार को मंत्रालय में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये गठित कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर विचार किया गया और राज्य सरकार को किए जाने वाले अनुशंसा के प्रमुख बिंदु में शामिल किया गया. बैठक में शाली त्यागी बालिकाओं को एक बार भी विद्यालय की ओर वापस लेने के लिए विकल्पों पर भी विचार किया गया. बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो सकीं, वहीं बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह उपस्थित थी. नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीतमी प्रतिमा बागरी बैठक में वर्चुवली शामिल हुईं. समिति ने इस दौरान प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाओं तथा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता एवं योजनाओं में अपेक्षित बदलाव पर विस्तृत चर्चा की. कमेटी की अगली बैठक अब जून में होगी.

7 दिन झुलसाएगी गर्मी

45 डिग्री से 46 डिग्री तक प्रदेश में तापमान

▸ हीटवेव की चपेट में पूरा मध्यप्रदेश

इंदौर, 19 मई . मध्यप्रदेश इस बार पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है.

इंदौर, भोपाल सहित अधिकांश शहरों में दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल, टीकमगढ़, छतरपुर और खजुराहो समेत कई इलाकों में सीवियर हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. ई दिव्या सुरेंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में ऐसा कोई मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे बारिश या थंडरस्टॉर्म की संभावना बन सके. अगले सात दिनों तक तापमान में राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार 45 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है.

25 मई से शुरू होने वाले नौतपा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. मौसम विभाग का कहना है कि नौतपा कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, लेकिन वर्तमान मौसम पैटर्न को देखते हुए गर्मी और ज्यादा तीखी हो सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक मई महीने में इस बार बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां काफी कम रही हैं, जबकि पिछले साल इसी दौरान कई जिलों में प्री-मानसून बारिश हुई थी.

> भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. बाहर निकलने पर छाता, टोपी या गमछे का उपयोग करने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की हिदायत दी गई है. डॉक्टरों ने ओआरएस, नींबू पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय पदार्थ लेने तथा हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

96 साल से टूट रहे 6 परिवारों के घर, इस बार तो हो जाएंगे बेघर

- सती गेट चौड़ीकरण पर उठे सवाल
- रसूखदारों के स्थान बचाने से बवाल
- दोनों ओर से चौड़ीकरण कर द्वार को सेंटर में लाने की मांग

प्रमोद व्यास

उज्जैन. ऐतिहासिक सती गेट क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। क्षेत्र के रहवासियों और व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1931 से अब तक लगभग चार बार सड़क चौड़ीकरण किया गया, हर बार केवल एक ही दिशा से भूमि लेकर मकान और दुकानों को प्रभावित किया गया. अब कंठाल चौराहे से खड़े हनुमान और छत्री चौक तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण में भी फिर उन्हीं परिवारों की दुकानों और भवनों पर निशान लगाए गए हैं, जिन्होंने पहले भी शहर हित में अपनी भूमि छोड़ी थी.

नवभारत से चर्चा में रहवासियों ने कहा कि वे शहर के विकास, सुगम यातायात और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के पूर्ण समर्थक हैं. सतीगेट, माता मंदिर और शहर के विकास के लिए आवश्यकता पड़े तो वे अपनी पूरी जमीन देने को भी तैयार हैं, बार-बार एक ही पक्ष से जमीन कटान किया जाना उन्हें पीड़ा दे रहा है. उनका कहना है कि दूसरी ओर से कभी चौड़ीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण ऐतिहासिक सतीगेट द्वार और मंदिर एक तरफ खिसक गए हैं.

तो सती गेट आएगा बीच में- क्षेत्रवासियों के अनुसार यदि दोनों दिशाओं से समान रूप से थोड़ी-थोड़ी भूमि लेकर सड़क का विस्तार किया जाए तो सतीगेट द्वार और मंदिर मार्ग के केंद्र में आ जाएंगे. इससे ऐतिहासिक धरोहर का स्वरूप और अधिक भव्य दिखाई देगा तथा कंठाल से गोपाल मंदिर तक सीधा दृश्य मार्ग बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में भी सुविधा होगी.

96 वर्ष पहले भूमि दान- रहवासियों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि कुछ परिवारों ने लगभग 96 वर्ष पूर्व भी जनहित में भूमि दान की थी. इसके बाद भी वर्षों में कई बार चौड़ीकरण के दौरान उन्होंने अपनी दुकानों और भवनों का हिस्सा छोड़ा. अब पुन: उन्हीं परिवारों को प्रभावित किए जाने से वे स्वयं को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

नया मापांकन किया जाए- रहवासियों ने मांग की है कि पूर्व में किए गए भूमि त्याग को अभिलेखों में शामिल किया जाए, संपूर्ण मार्ग का निष्पक्ष पुनर्माप किया जाए, दोनों पक्षों की वास्तविक स्थिति को समान रूप से देखा जाए तथा स्थानीय व्यापार, भवन सुरक्षा और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नई केंद्र रेखा निर्धारित की जाए.

सिंहस्थ के लिए व्यापक सड़क विस्तार- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत बड़े पैमाने पर सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है. कोयला फाटक, गाड़ी अड्डा, कोतवाली क्षेत्र, कंठाल, सतीगेट, खड़े हनुमान, सराफा, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और ढाबा रोड सहित अनेक क्षेत्रों में मार्ग विस्तार के कार्य जारी हैं. यह वही मार्ग हैं जहां भगवान महाकाल की सवारी, धार्मिक शोभायात्राएं, सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजन, रैलियां और जुलूस निकलते हैं.

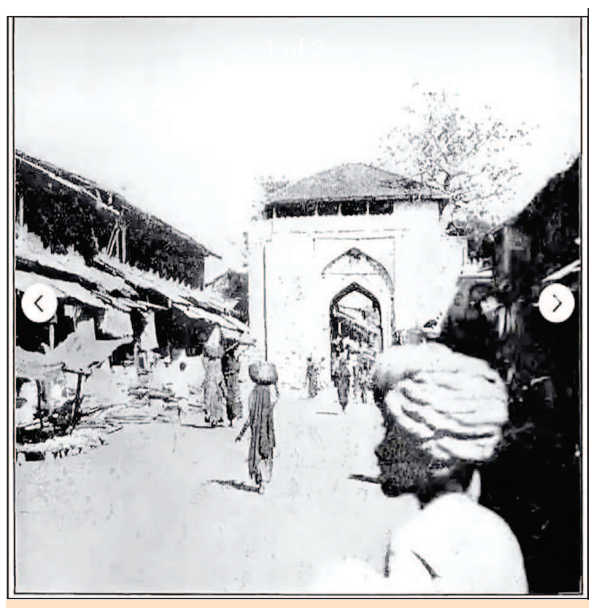

कलेक्टर व आयुक्त को सौंपा विस्तृत आवेदन

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि गोपाल मंदिर मार्ग स्थित भवनों को दिनांक 26 फरवरी 2026 को मार्ग चौड़ीकरण का नोटिस दिया गया. आवेदन में कहा गया कि उनकी दिशा से पूर्व में लगभग 15 फीट तक भूमि सड़क के लिए छोड़ी जा चुकी है. पुराने दस्तावेज, नक्शे और पूर्व कटान से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए हैं.

इनका कहना है...

क्षेत्र के रहवासियों ने सती गेट के आसपास का मामला मेरे संज्ञान में दिया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. सतीगेट के आसपास कब-कब कितना चौड़ीकरण हुआ है और अब वहां क्या स्थिति है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है.

- अभिलाष मिश्रा, नगर निगम आयुक्त उज्जैन

मुख्यमंत्री के नाम भी भेजा गया ज्ञापन

क्षेत्र के रहवासियों और व्यापारियों ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम भी ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन में कहा गया है कि उज्जैन के ऐतिहासिक सतीगेट क्षेत्र के लोग वर्षों से विकास कार्यों में सहयोग करते आ रहे हैं और बिना मुआवजा लिए अपने हाथों से मकान-दुकानों का हिस्सा हटाने तक को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए.

छह दुकानों साइड से भी चौड़ीकरण की मांग

रहवासियों की मांग है कि सती गेट के दूसरी ओर स्थित छह दुकानों की दिशा से भी समान रूप से चौड़ीकरण किया जाए. उनका कहना है कि इससे सड़क विस्तार संतुलित होगा, ऐतिहासिक द्वार ठीक मध्य में आएगा और विकास कार्य में पारदर्शिता तथा न्याय का भाव दिखाई देगा. क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट किया है कि वे विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते, बल्कि केवल इतना चाहते हैं कि मार्ग चौड़ीकरण निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित तरीके से किया जाए, ताकि शहरहित के साथ न्याय भी सुनिश्चित हो सके.

शिवम वर्मा फेम इंडिया सूची में शामिल

लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में किया शामिल

04 बेहतरीन कार्यशैली के कारण किया गया सूची में शामिल

इंदौर, 19 मई . फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिए गए हैं.

इसमें मप्र से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सतना कलेक्टर सतीश कमार, नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र

सिंह है. सर्वे में देशभर के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के कामकाज, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन किया गया. इसके बाद लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है.

जनसरोकार से जुड़े पहलू भी सर्वे का हिस्सा

फेम इंडिया के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, संकट प्रबंधन, जनसंपर्क, नवाचार, जवाबदेही, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 10 प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया. इसके अलावा विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और जनसरोकार से जुड़े पहलुओं को भी सर्वे का हिस्सा बनाया गया.

आरएनटी मार्ग पर कॉर्पोरेट हाउस में दिल्ली पुलिस की दबिश

- बिजेटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में खंगाला रिकॉर्ड
- दिल्ली में दर्ज किसी बड़े मामले में कंपनी का नाम आया सामने

नव भारत न्यूज

इंदौर. आरएनटी मार्ग स्थित कॉर्पोरेट हाउस में दिल्ली पुलिस ने अचानक छापा मारते हुए बिजेटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को घेरे में ले लिया. मंगलवार दोपहर पहुंची टीम ने कंपनी के दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले.

शहर के व्यस्त आरएनटी मार्ग पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने कॉर्पोरेट हाउस बिल्डिंग में दबिश दी. टीम सीधे बिजेटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंची और वहां सर्चिंग शुरू कर दी. पुलिस कंपनी के वित्तीय लेन-देन, डिजिटल डेटा और अन्य अहम दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है. ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है. कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा, जिससे स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों को भी पहले से जानकारी नहीं मिल सकी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में दर्ज किसी बड़े मामले के तार इस कंपनी से जुड़े होने की आशंका है. इसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम ने यहां कार्रवाई की है. हालांकि, अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन देर शाम तक कार्रवाई जारी रहने की संभावना है.

पेज एक का शेष

पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का हुआ निधन

1934 को देहरादून में जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की. उन्हें छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रभावित किया. उन्होंने 1954 से 1990 तक भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में 36 साल तक सेवा दी. इस दौरान उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई, रेजीमेंट कमांडर रहे, सेना में चीफ इंजीनियर और आर्मी मुख्यालय में एडिशनल मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. वह 1991 में पहली बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे. इसके बाद उन्होंने 1998, 1999, 2004 और 2014 में भी लोकसभा चुनाव जीता. संसद में रहते हुए उन्होंने भाजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, गृह मामलों की समिति समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. वर्ष 2014 से 2018 तक वह रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे.

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती मिली.

2. स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर फोकस समझौतों का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और सतत विकास को बढ़ावा देना है.

3. अनुसंधान परिषदों का सहयोग सीएसआईआर और नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल के बीच जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा, महासागर विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी.

4. अपतटीय पवन ऊर्जा और कार्बन प्रबंधन- सीएसआईआर ने नॉर्वेजियन संगठन एसआईएनटीईएफ के साथ 2026-2029 तक सहयोग समझौता किया.

5. अकादमिक और हरित परिवर्तन सहयोग- एसीएसआईआर और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान एवं संयुक्त अनुसंधान पर समझौता.

6. भूविज्ञान आधारित अवसंरचना समाधान- सीएसआईआर-एनजीआरआई और एमराल्ड जियोमॉडलिंग ने भारत में बड़े अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 5 साल का सहयोग समझौता किया.

राइस मिल में आग लगने से एक श्रमिक की मौत

सतना. जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सतना-अमरपाटन मार्ग पर संचालित एक राइस मिल में आग लगने से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार देर रात को राइस मिल में धान की भूसी से तेल निकालने का कार्य चल रहा था. इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

पश्चिम रेलवे

कोच शौचालय का उन्नयन

मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, कैरिज मरम्मत कार्यशाला, पश्चिमी रेलवे, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 निविदा सूचना संख्या: WRPL - ME - EST - 633541 - C दिनांक 14.05.2026 कार्य का नाम और स्थान: "नॉन-एसी एलएचबी कोचों का शौचालय उन्नयन" अनुमानित लागत: रू. 48,10,29,872.00/- बयाना राशि: 96,20,600.00/-. ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय: ई-बोली जमा करने की तिथि: 12.09.2026, 11:00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि: 12.09.2026 को 11:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें www.ireps.gov.in **0119**

Like us on : facebook.com/WesternRly

उठाए सवाल | बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग

सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल : पटवारी

भोपाल, 19 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सोशल मीडिया प्रचार और आयोजनों के माध्यम से विकसित मध्यप्रदेश की कृत्रिम तस्वीर पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. पटवारी ने कहा कि प्रदेश में लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं. कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों पद अब भी रिक्त पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है.

उन्होंने हाल ही में सामने आई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 788 सरकारी स्कूलों में अब भी छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं हैं. इसे उन्होंने छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला बताया. कांग्रेस नेता का आरोप है कि छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण हेतु 2.30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कई स्थानों पर यह धनराशि पुताई और अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई, जिससे छात्राओं को असुरक्षित और अस्वच्छ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है.

अशोकनगर, राजगढ़ सहित अन्य जिलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए पटवारी ने कहा कि इससे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छ भारत' जैसे नारों की वास्तविकता उजागर हो गई है.

> उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, आधारभूत सुविधाओं की कमी और विभिन्न योजनाओं के तहत हुए खर्च का ब्यौरा देते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. साथ ही शौचालय निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - रतलाम मंडल -पश्चिम रेलवे ने पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को **IREPS** वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है। केटलॉग सं. लीजिंग-आर टी एम- 26-03, अनुबंध का प्रकार - Leasing of SLR Compartment, लॉट नं. : Train No. - 11125-SLR-R1-RTM-GWL, 59387-SLR-R1-NAD-INDB, 19303-SLR-F2-INDB-BPL, 21125-SLR-R1-RTM-BIX, 19303-SLR-R1-INDB-BPL, 19321-SLR-R1-INDB-PNBE, 59387-SLR-F1-NAD-INDB, 21125-SLR-F1-RTM-BIX, 22984-SLR-F1-INDB-KOTA, 11125-SLR-F1-RTM-GWL, 19303-SLR-F1-INDB-BPL, 19343-SLR-R1-INDB-NIR, 22984-SLR-R1-INDB-KOTA, 14802-SLR-F1-INDB-JU, 19313-SLR-F1-INDB-PNBE, 14115-SLR-F1-DADN-PRYJ, 19343-SLR-F2-INDB-NIR, 19343-SLR-F1-INDB-NIR, 12913-SLR-F1-INDB-NGP, 19307-SLR-F1-INDB-UHL, 14802-SLR-R1-INDB-JU, 20416-SLR-R1-INDB-BSB, 20414-SLR-F1-INDB-BSB, 19307-SLR-R1-INDB-UHL, 19817-SLR-F1-RTM-AF, 19313-SLR-R1-INDB-PNBE, 19817-SLR-R1-RTM-AF, 20917-SLR-F1-INDB-PURI, 20414-SLR-R1-INDB-BSB. अनुबंध की अवधि - 03 वर्ष, ई -नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिए ई-नीलामी **दिनांक 04.06.2026 को 10:00 बजे प्रारंभ होगी**। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंध करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-059

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60